

दैनिक भारत कि

# तामीर

संपादक - काझी मक्कदूम शफीउद्दीन [hinditameer@gmail.com](mailto:hinditameer@gmail.com)

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

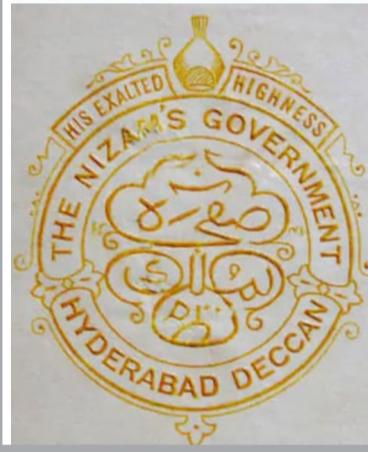
## हैदराबाद गजट की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में मसौदा को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा

### न्यायालयीन कसौटी पर टिकने वाला निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है-राधाकृष्ण विखेपाटील

मुंबई से जमीर काझी की रिपोर्ट

इसके लिए विधि विशेषज्ञों और महाधिवक्ता के साथ विस्तृत चर्चा चल रही है, और ऐसा निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है जो न्यायालयीन कसौटी पर खार उतरे। यह जानकारी उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील ने सोमवार को पत्रकारों को दी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटील के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार द्वारा तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक के बाद विखे-पाटील ने कहा, हैदराबाद गजट की सिफारिशों को लागू करने के लिए मसौदा जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

न्यायालयीन कसौटी पर टिकने वाला निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, मुंबई उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के कारण प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई है।



उहोंने आगे कहा, पिछले तीन दिनों से आंदोलनकारियों की मांगों के संबंध में विभिन्न विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा चल रही है। आंदोलन के दूसरे दिन न्यायमूर्ति संदीप शिंदे और हमारे अधिकारी आंदोलन स्थल पर गए थे। उनका जापानी भी प्राप्त हो चुका है। आज सुबह हुई बैठक में स्वयं मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री उपस्थित थे। इसके अलावा महाधिवक्ता और न्यायमूर्ति संदीप शिंदे भी मौजूद थे। बैठक का मुख्य ध्यान हैदराबाद गजट की सिफारिशों को लागू करने पर था। आज मुंबई उच्च

न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर होने के कारण महाधिवक्ता को वहां जाना पड़ा। न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान कथा निर्देश दिए हैं, इसे देखने के बाद महाधिवक्ता के साथ पिर से बैठक होगी। इसके बाद ही मसौदे को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।

हैदराबाद गजट की सिफारिशों के संदर्भ में दैनिक तामीर हिंदी की भूमिका:

कल दैनिक तामीर हैदराबाद गजट की सिफारिशों को विस्तार से प्रस्तुत किया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों ने लागू करने पर था। आज मुंबई उच्च

पढ़ा, समझा और इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। यह एक सकारात्मक पहल है, जो मराठा आरक्षण के मुद्रे पर चल रहे आंदोलन और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हैदराबाद गजट की सिफारिशों की अंमलबजावाणी पर महाराष्ट्र सरकार

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटील के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समाधान के लिए महाराष्ट्र चल रही है ताकि निर्णय न्यायालयीन कसौटी

हैदराबाद गजट की सिफारिशों को लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।

प्रमुख बिंदु:

मसौदे की प्रगति: हैदराबाद गजट की सिफारिशों को लागू करने के लिए मसौदा

पर एक सकारात्मक पहल है, जो मराठा आरक्षण के मुद्रे पर चल रहे आंदोलन और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

### दैनिक तामीर की भूमिका

दैनिक तामीर हिंदी ने हैदराबाद गजट की सिफारिशों को विस्तार से प्रस्तुत किया, जिसे महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों ने सराहा। यह सकारात्मक पहल सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद को बढ़ाने में सहायक रिश्व हुई है। महाराष्ट्र सरकार हैदराबाद गजट की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

सरकारी प्रयास: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में इस मुद्रे पर गहन विचार-विमर्श हुआ। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे और अन्य अधिकारियों ने आंदोलन स्थल का दैरा कर आंदोलनकारियों का जापान प्राप्त किया।

न्यायालयीन बाधा: मुंबई उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के कारण प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई है। महाधिवक्ता इस याचिका की सुनवाई के निर्देशों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।



### न्यायालयीन कसौटी पर टिकने वाला निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है-राधाकृष्ण विखेपाटील



## मुंबई की सभी सड़कें आजाद मैदान को छोड़कर खाली करें: हाई कोर्ट ने सरकार को फटकारा

### आज पिर होगी सुनवाई

जमीर काझी

मुंबई, पिछले चार दिनों से मुंबई में आजाद मैदान और दक्षिण मुंबई के विभिन्न स्थानों पर डटे मराठा आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को संभालने में लापत्ता बरी नहीं है और आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की अधिक सड़कों पर चल रहे आंदोलनकारियों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कंडे शब्दों में फटकारा

## उद्दृ दैनिक तामीर के २५ वें साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

